

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
16.03.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2471 का उत्तर

राष्ट्रीय रेल योजना विज़न-2030

2471. श्री मनोज कोटक:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय रेल ने भारत-2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विज़न 2024 शुरू किया है;
- (घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) क्या सरकार ने नए तीव्र गति रेल गलियारों को चिह्नित किया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय रेल योजना विज़न- 2030 के संबंध में 16.03.2022 को लोकसभा में श्री मनोज कोटक तथा श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे के अतारांकित प्रश्न सं. 2471 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ख) भारतीय रेल ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना-2030 तैयार की है। 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली तैयार करने की योजना है। राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालनिक क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों दोनों के आधार पर रणनीतियां तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य मांग से पहले क्षमता का सृजन करना है, जिसके परिणामस्वरूप 2050 तक भविष्य की मांग को पूरा भी किया जा सकेगा और माल यातायात में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी 45% तक बढ़ेगी, और इसे बनाए रखना है।

राष्ट्रीय रेल योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

- माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालनिक क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों दोनों के आधार पर रणनीतियां तैयार करना।
- माल गाड़ियों की औसत गति को बढ़ाकर 50 किमी प्रति घंटा करके माल ढुलाई के पारगमन समय को काफी कम करना।
- राष्ट्रीय रेल योजना के भाग के रूप में, 2024 तक 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों को मल्टी ट्रेक करना, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर 160 किमी प्रति घंटे तक गति का उन्नयन, अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्णिम विकर्ण (जीक्यू/जीडी) मार्गों पर 130 किमी प्रति घंटे तक गति का उन्नयन और सभी जीक्यू/जीडी मार्ग पर सभी समपारों को समाप्त करना जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विजन 2024 शुरू किया गया है।
- नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पहचान करना।
- नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करना।

- यात्री यातायात के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए चल स्टॉक की आवश्यकता के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता का आकलन करना।
- 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) और माल ढुलाई में मॉडल शेयर बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता का आकलन करना।
- पूंजी में कुल निवेश का आकलन करना जो आवधिक विवरण के साथ अपेक्षित होगा।
- चल स्टॉक के संचालन और स्वामित्व, माल ढुलाई और यात्री टर्मिनलों के विकास, रेलपथ अवसंरचना के विकास/संचालन आदि जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी इत्यादि।

(ग) और (घ) : जी हां। 3750 किमी. की कुल लंबाई की 58 अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं जिसकी कुल लागत 39,663 करोड़ रु. तथा 6913 किमी. की 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं जिसकी कुल लागत 75,736 करोड़ रु. है, को 2024 तक पूर्ण करने के लिए चिन्हित किया गया है।

(ड) और (च) : वर्तमान में, मुंबई- अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) (508 किमी.) परियोजना देश में हाई स्पीड रेल (एचएसआर) की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है जो जापान सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से निष्पादन के अधीन है।

इसके अलावा, निम्नलिखित सात हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रक्रियाधीन है:

दिल्ली- वाराणसी

दिल्ली- अहमदाबाद

मुंबई- नागपुर

मुंबई- हैदराबाद

चैन्नई- मैसूर

दिल्ली- अमृतसर

वाराणसी- हावड़ा

किसी भी एचएसआर परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय डीपीआर के परिणाम, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और वित्तपोषण विकल्पों पर निर्भर करता है।
